

ment for inter State movement of levy free rice on State Government account.

(c) and (d) Central Government have received requests from time to time from the Government of Kerala to allow them to purchase 30,000 to one lakh tonnes of levy free rice from the surplus States. Taking into account availability in the surplus States, Kerala Government were allowed to purchase during 1982-83 Kharif marketing season, 75,000 tonnes of rice in all, 15,000 tonnes from Punjab/Haryana, and 60,000 tonnes from Andhra Pradesh.

Increase In Pure Ghee Prices

*179. SHRI MOHANLAL PATEL :
SHRI CHINTAMANI JENA :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that pure ghee prices are shooting up day by day not only in private sector but in public sector also;

(b) if so, the reasons for the increase in pure ghee prices throughout the country; and

(c) the steps being taken to check it?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) There has been some increase in the prices of Desi Ghee both in private and public sectors.

(b) The production and marketing of Desi Ghee is largely in the hands of private-sector Desi ghee is also not subject to any price control. Increase in prices of desi ghee appears to have been influenced by the behaviour of the prices of edible oils, feed, fodder and milk and prices of other essential commodities.

(c) Government has consistently undertaken a number of programmes in the Central sector and State Plans for development of livestock and dairies for increasing production of milk and to maintain the price of milk and milk products at reasonable levels keeping the interest of producers and consumers in view.

सुरत, गुजरात में कमान्ड एरिया
डेवलपमेंट के लिए सहायता

*180. श्री छीतू भाई गामित : क्या सिंचाई

मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में उकाई काकाडापुर कमान्ड एरिया डेवलपमेंट अथारिटी, सुरत, गुजरात ने भारत सरकार से कमान्ड एरिया के विकास की योजना में सहायता करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त योजना के लिए कुल कितनी राशि की सहायता की मांग की गई है और भारत सरकार द्वारा कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) गुजरात सरकार के अनुरोध पर उर्कई ककरापार परियोजना 1974 से केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, स्थापना, सर्वेक्षणों, फील्ड चैनलों का निर्माण करने, भूमि समतल करने, फील्ड ड्रेनों का निर्माण करने तथा वारंबंदी लागू करने जैसी आइटमों पर हुए व्यय के लिए केन्द्र द्वारा राज्य सरकार को बराबर की सहायता दी जाती है।

राज्य सरकार से कार्यक्रम में सम्मिलित सभी परियोजनाओं के लिए दावे प्राप्त होते हैं न कि प्रत्येक परियोजना के लिए अलग-अलग। गुजरात सरकार ने वर्ष 1983-84 के लिए 256.22 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता मांगी थी। केन्द्रीय सहायता दो किस्तों में दी गई है, पहली किस्त पिछले वर्ष में व्यय न की गई शेष राशि को समायोजित करते हुए एक वर्ष में देय राशि की लगभग आधी थी। 1982-83 में गुजरात सरकार को दी गई कुल राशि में से व्यय न की गई 30.07 लाख रु० की शेष राशि को हिसाब में लेते हुए, 102.55 लाख रुपए की राशि दी गई है। जनवरी, 1984 तक वास्तविक कार्य-निष्पादन तथा वित्तीय वर्ष